SAFALTA CLASS™

An Initiative by अमर उजाला

INDIAN

POLITY

CTET ⇒ P-2

SST

BY – SUJEET BAJPAI SIR

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमर उजाला

उद्देशिका | प्रस्तावना

Preamble of the Constitution

→ Consti of USA → 1st written Consti. of World

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमरउजाला

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a [1][**SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC**] and to secure to all its citizens :

JUSTICE, social, economic and political;

LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;

EQUALITY of status and of opportunity and to promote among them all;

FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the [2][unity and integrity of the Nation];

IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November, 1949 do **HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.**

भारत का संविधान
उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक **संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य** बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक **न्याय**,

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की **स्वतंत्रता**,

प्रतिष्ठा और अवसर की **समता**
प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन **सब में** व्यक्ति की गरिमा और
राष्ट्र की एकता और अखंडता
सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर **अपनी इस संविधान सभा में** आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को **एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।**

Ingredients of the Preamble The Preamble reveals four ingredients or components:

1.

Source of authority of the Constitution: The Preamble states that the Constitution derives its authority from the people of India.

प्रस्तावना प्रस्तावना से चार अवयवों या घटकों का पता चलता है:

1. संविधान के अधिकार का स्रोत:

प्रस्तावना में कहा गया है कि संविधान भारत के लोगों से अपना अधिकार प्राप्त करता है ।

2.

Nature of Indian State: It declares India to be of a sovereign, socialist, secular democratic and republican polity.

3.

Objectives of the Constitution: It specifies justice, liberty, equality and fraternity as the objectives.

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमरउजाला

2.

भारतीय राज्य की प्रकृति:

यह भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक और रिपब्लिकन राजनीति को घोषित करता है ।

3.

संविधान के उद्देश्य:

यह न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को उद्देश्यों के रूप में निर्दिष्ट करता है ।

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमर उजाला

4.

Date of adoption of the Constitution:

It stipulates November 26, 1949 as the date.

v/s

26 Jan 1950

संविधान को अपनाने की तिथि:

इसमें 26 नवंबर, 1949 को तारीख निर्धारित की गई है।

Key Words in the Preamble Certain key words—

> Sovereign संप्रभु => हस्तक्षेप

Not Interference in affairs of India.

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमर उजाला

Key Words in the Preamble Certain key words—

> Soc. / समाजवादी ⇒ mixed eco.

> Secular ⇒ पंथ निरपेक्ष

> Democratic ⇒ जनता का शासन

Key Words in the Preamble Certain key words—

Britain (X)

Republic ⇒ (गणतंत्र)

USA ✓

Head of the state will be elected by people directly or (Indirectly).

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमर उजाला

NOTE:

1. The Preamble is neither a source of power to legislature nor a prohibition upon the powers of legislature.
2. It is non-justiciable, that is, its provisions are not enforceable in courts of law.

नोट:

1. प्रस्तावना न तो विधायिका को शक्ति का स्रोत है और न ही विधायिका की शक्तियों पर प्रतिबंध है ।

2. यह गैर-बदनाम है, अर्थात न्यायालयों में इसके प्रावधान लागू नहीं हैं।

Amendability of the Preamble:

Yes

The Preamble has been amended only once so far, in 1976, by the 42nd Constitutional Amendment Act, which has added three new words—Socialist, Secular and Integrity—to the Preamble.

प्रस्तावना की संशोधन:

हाँ

प्रस्तावना में 1976 में 42 वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा केवल एक बार संशोधन किया गया है, जिसमें तीन नए शब्दों-समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को प्रस्तावना में जोड़ा गया है ।

Union and its Territory

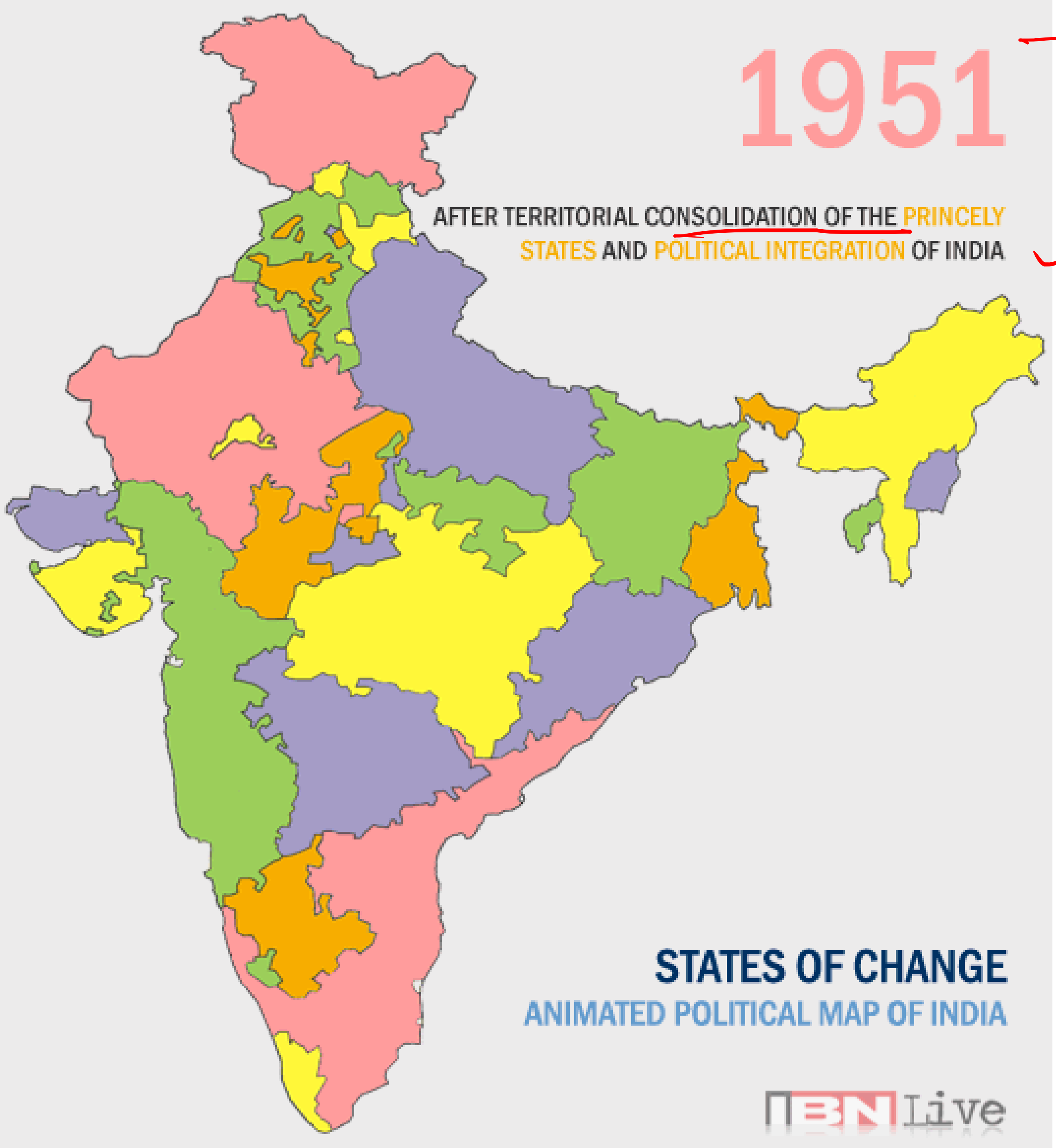

1947

धर Dhar

JVP

According to Article 1, the territory of India can be classified into three categories:

India that is Bharat shall be union of states
राज्यों का संघ

1. Territories of the states
2. Union territories
3. Territories that may be acquired by the Government of India at any time.

अनुच्छेद 1 के अनुसार, भारत के क्षेत्र को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता हैं:

1. राज्यों के प्रदेशों
2. केंद्र शासित प्रदेश
3. ऐसे क्षेत्र जो किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहीत किए जा सकते हैं।

Article 2 grants two powers to the Parliament:

(a) the power to admit into the Union of India new states; and

(b) the power to establish new states.

अनुच्छेद 2 संसद को दो शक्तियां प्रदान करता है:

(क) भारत के नए राज्यों के संघ में प्रवेश करने की शक्ति; और

(ख) नए राज्यों की स्थापना की शक्ति ।

Article 3, on the other hand, relates to the formation of or changes in the existing states of the Union of India.

POK

In other words, Article 3 deals with the internal re-adjustment of the territories of the constituent states of the Union of India.

दूसरी ओर अनुच्छेद 3 भारत संघ के मौजूदा राज्यों के गठन या बदलाव से संबंधित है।

दूसरे शब्दों में, अनुच्छेद 3 भारत संघ के घटक राज्यों के क्षेत्रों के आंतरिक पुन समायोजन से संबंधित है ।

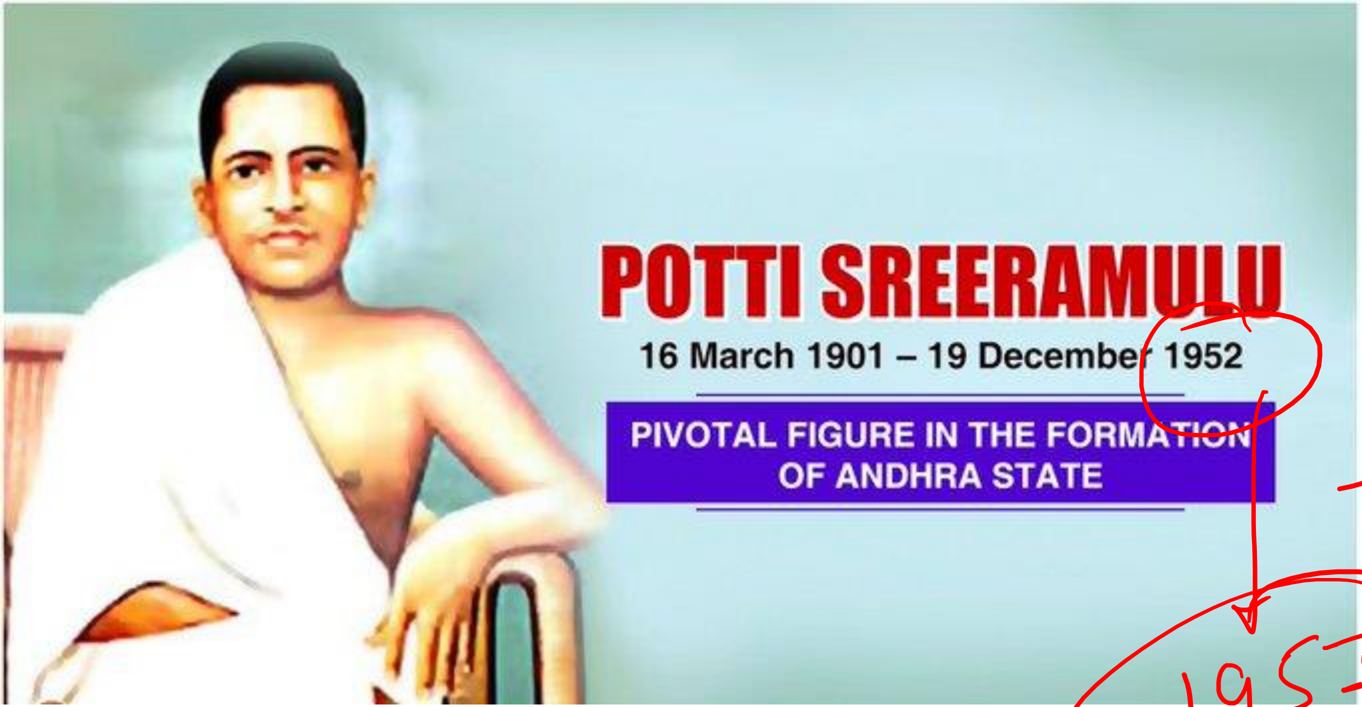

श्री रामुलु

Andhra

1953

1953

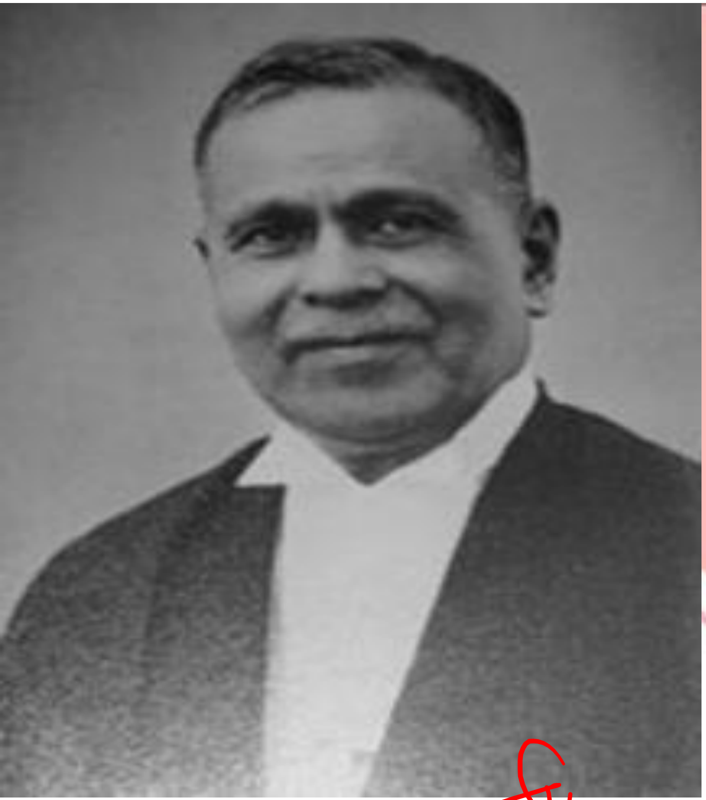

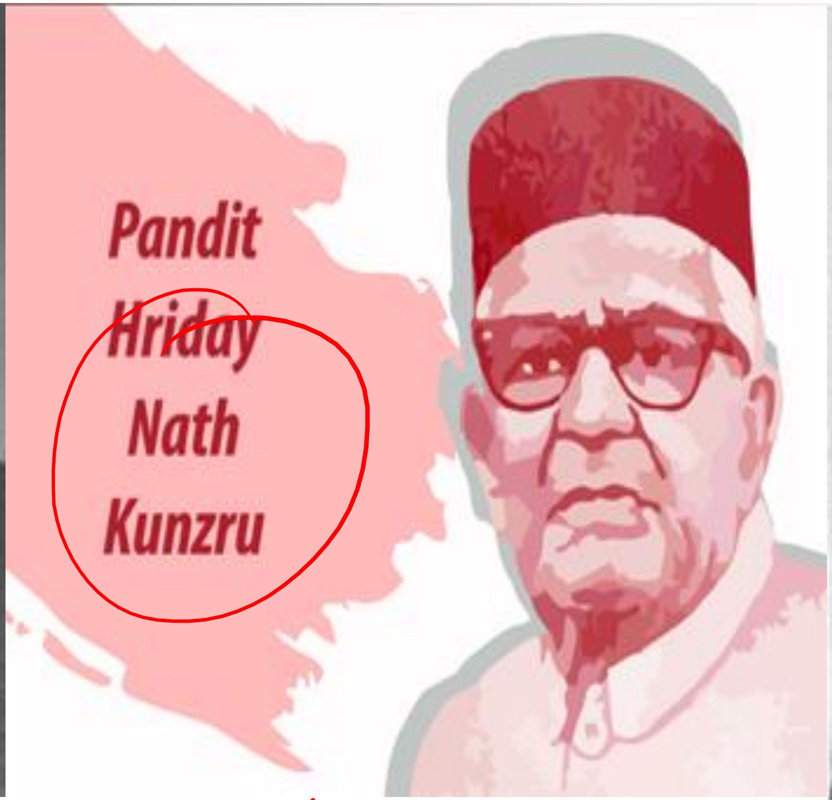

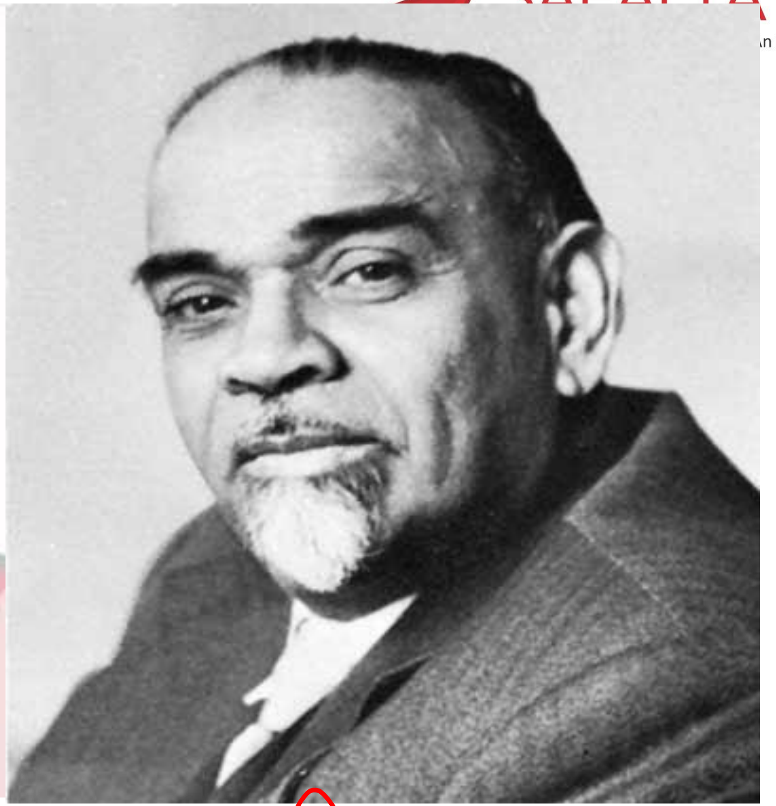

फजल अली + पणिक्कर

Dhar Commission and JVP Committee:

The integration of princely states with the rest of India has purely an ad hoc arrangement. There has been a demand from different regions, particularly South India, for reorganisation of states on linguistic basis.

धर आयोग और जेवीपी समिति:

शेष भारत के साथ रियासतों के एकीकरण में विशुद्ध रूप से तदर्थ व्यवस्था है ।

भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए विभिन्न क्षेत्रों, विशेषकर दक्षिण भारत से माँग की गई है।

Accordingly, in June 1948, the Government of India appointed the Linguistic Provinces Commission under the chairmanship of S K Dhar to examine the feasibility of this.

The commission submitted its report in December 1948 and recommended the reorganisation of states on the basis of administrative convenience rather than linguistic factor.

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमर उजाला

तदनुसार, जून 1948 में भारत सरकार ने इसकी व्यवहार्यता की जांच करने के लिए एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की।

आयोग ने दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और भाषाई फैक्टर के बजाय प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की।

This created much resentment and led to the appointment of another Linguistic Provinces Committee by the Congress in December 1948 itself to examine the whole question afresh.

इससे काफी नाराजगी पैदा हुई और दिसंबर 1948 में ही कांग्रेस द्वारा एक और भाषाई प्रांत समिति की नियुक्ति कर इस पूरे सवाल की नए सिरे से जांच की गई।

It consisted of Jawaharlal Nehru, Vallabhbhai Patel and Pattabhi Sitaramayya and hence, was popularly known as JVP Committee.

It submitted its report in April 1949 and formally rejected language as the basis for reorganisation of states.

इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लाहभाई पटेल और पट्टाभि सीतारामैया शामिल थे और इसलिए उन्हें जेवीपी कमेटी के नाम से जाना जाता था ।

इसने अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और औपचारिक रूप से भाषा को राज्यों के पुनर्गठन के आधार के रूप में अस्वीकार कर दिया ।

However, in October 1953, the Government of India was forced to create the first linguistic state, known as Andhra state, by separating the Telugu speaking areas from the Madras state.

This followed a prolonged popular agitation and the death of Potti Sriramulu, a Congress person of standing, after a 56-day hunger strike for the cause.

हालांकि अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को तेलुगु भाषी क्षेत्रों को मद्रास राज्य से अलग करके आंध्र राज्य के नाम से जाना जाने वाला पहला भाषाई राज्य बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा।

इसके बाद लंबे समय तक लोकप्रिय आंदोलन चला और कांग्रेस के खड़े व्यक्ति पोट्टी श्रीरामुलु की मौत के बाद 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद इस कारण से मौत हो गई ।

Fazl Ali Commission

The creation of Andhra state intensified the demand from other regions for creation of states on linguistic basis.

This forced the Government of India to appoint (in December 1953) a three-member States Reorganisation Commission under the chairmanship of Fazl Ali to re-examine the whole question.

फजल अली आयोग

आंध्र राज्य के निर्माण से भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण के लिए अन्य क्षेत्रों से मांग तेज हो गई।

इससे भारत सरकार को (दिसंबर 1953 में) फजल अली की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग नियुक्त करने को मजबूर होना पड़ा और पूरे सवाल की फिर से जांच की गई।

Its other two members were K M Panikkar and H N Kunzru.

It submitted its report in September 1955 and broadly accepted language as the basis of reorganisation of states. But, it rejected the theory of 'one language–one state'.

Its view was that the unity of India should be regarded as the primary consideration in any redrawing of the country's political units.

इसके अन्य दो सदस्य केएम पाणिकर और एच एन कुंजरू थे।

इसने सितंबर 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और राज्यों के पुनर्गठन के आधार के रूप में मोटे तौर पर भाषा को स्वीकार किया।

लेकिन, इसने 'एक भाषा-एक राज्य' के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। इसका विचार यह था कि देश की राजनीतिक इकाइयों को फिर से तैयार करने में भारत की एकता को प्राथमिक विचार माना जाना चाहिए।